

**SHRI K. C. PANT :** Considering the situation in West Bengal and Bihar, I think, the forces there with the arms that were referred to by my hon. friend, did succeed in maintaining law and order during the poll period. It was with a view to prevent a few stray incidents in the light of the overall situation there and a deliberate attempt being made by some elements to disrupt the polls. I have no information whether any prisoners were released and they were given arms.

**श्री राम सहाय पांडे :** बहुत से प्रदेशों में विशेष कर पश्चिमी बंगाल में क्या यह रिपोर्ट आपको मिली है कि सी० पी० एम० के कार्यकर्ताओं के द्वारा बोटों को रोका गया और अशांति फैलाई गई ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसमें जाना मैं नहीं चाहता। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट मिली हैं।

**SHRI SAMAR MUKHERJEE :** May I know how many were murdered or killed during the election period ?

**SHRI K. C. PANT :** I require notice for that.

**SHRI SAMAR MUKHERJEE :** He gave a statement in the Rajya Sabha that 30 had been killed Is it a fact ? It had appeared in the press.

**MR. SPEAKER :** Next Question.

**छोटे समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की योजना**

\*269. **श्री रामाबतार शाल्मी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसे समाचारपत्रों की, राज्यवार, संख्या क्या है जिन्हें सबसे कम पढ़ा है तथा पढ़ाने की भाषा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बर्नबीर सिंह) (क) और (ख). प्रचार आवश्यकताओं तथा जनराशि की उपलब्धि के अनुरूप छोटे समाचारपत्रों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस बारे में उठाए गए कदम दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (विवरण 'क')

(ग) वर्ष 1971-72 (31 दिसम्बर, 1971 तक) के दौरान, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के लिए 1,259 छोटे समाचारपत्रों का उपयोग किया गया था। इस संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (विवरण 'ख')

**विवरण 'क'**

(1) परिवार नियोजन, लघु बचत, राष्ट्रीय एकता जैसे व्यापक अभियानों के लिए छोटे समाचारपत्रों का यथासंभव उपयोग किया जाता है।

(2) बड़े आकार के विज्ञापन भाषाई समाचारपत्रों, जो आमतौर पर छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों की श्रेणी से सम्बन्धित होते हैं, को जारी किए जाते हैं और छोटे आकार के विज्ञापन बड़े अंग्रेजी समाचारपत्रों को दिए जाते हैं।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सच लोक सेवा आयोग, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा अन्य भर्ती विज्ञापन जो आमतौर पर बड़े पत्रों को दिए जाते हैं, अब उनका प्रभाव न बिगाड़ते हुए छोटे स्थान में दिए जाते हैं और इस प्रकार इससे जो बचत होती है वह छोटे समाचारपत्रों, अधिकशतक प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों को अधिक विज्ञापन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

(4) संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले पत्रों की सूची में वृद्धि कर दी गई है और उसमें कुछ और छोटे और मंझोले पत्र शामिल किए गए हैं।

(5) छोटे समाचारपत्रों को अब माउन्टेड स्टीरिओज दिए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप समाचारपत्रों की प्रति प्रविष्टि 4 रुपए से 5 रुपए तक की बचत होती है। उर्वर में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को स्टीरिओज के स्थान पर "चरबास" दिये जा रहे हैं।

(6) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई है कि वे अपने विज्ञापनों के लिए समाचारपत्रों का चयन करते समय छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों का विशेष ध्यान रखें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपने विज्ञापन बजट में उपयुक्त अनुपात में ऐसी अलग से व्यवस्था करे जिससे प्रादेशिक भाषाओं में छपने वाले छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों का अधिक उपयोग किया जा सके।

(7) उन विज्ञापन एजेंसियों, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से प्रत्यायित होने की इच्छा रखती हैं से यह अपेक्षित है कि वे छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति का यथासंभव पालन करे।

#### विवरण 'ख'

क्रम संख्या राज्य का नाम समाचारपत्रों की संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	36
2.	आसाम	17
3.	बिहार	37
4.	दिल्ली	248
5.	गुजरात	60
6.	हरियाणा	4

7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू तथा काश्मीर	34
9.	केरल	33
10.	मध्य प्रदेश	56
11.	महाराष्ट्र	172
12.	मैसूर	41
13.	उड़ीसा	12
14.	पंजाब	73
15.	राजस्थान	75
16.	तमिलनाडु	57
17.	उत्तर प्रदेश	150
18.	पश्चिम बंगाल	120
19.	संघ प्रशासित क्षेत्र	30

कुल संख्या : 1,259

श्री रामातार शास्त्री : सरकार ने समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कौन सा मापदंड तय किया है। कितने समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए जा रहे हैं उत विज्ञापनों में से कितना प्रतिशत बड़े समाचार पत्रों को दिया जा रहा है और कितना प्रतिशत छोटे समाचारपत्रों को दिया जा रहा है और उनमें भी कितना प्रतिशत पीरियाडिकलज को दिया जाता है।

श्री जर्मेबीर सिंह : समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने के लिए सरकार ने जो मापदंड रखे हैं, वे हैं समाचारपत्र की इफेक्टिव सर्कुलेशन यानी बंटने की संख्या क्या है। इसी प्रकार प्रकाशन की रेग्युलैरिटी।

पत्रकारिता के एविकस की समाचारपत्र द्वारा भाव्यता उसके-साथ-साथ सरकार ध्यान में रखती है कि समाचार पत्र की भाषा क्या है और किस क्षेत्र में वह पढ़ा जाता है। उसके बाद वह भी ध्यान में रखा जाता है कि विज्ञापन के लिए वह रेट की क्या मांग है।

श्री रामातार शास्त्री : मैंने यह पूछा है कि बड़े समाचार पत्रों की कितने प्रतिशत, छोटे

समाचारपत्रों को कितने प्रतिशत और पीरियाडिकल्ज को कितने प्रतिशत आप विज्ञापन दे रहे हैं ?

श्री बर्मबीर सिंह : अभी तक 60.84 जो हम लोगों ने इससे विज्ञापन दिए हैं वे छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को दिए हैं और 39.16 बड़े पत्रों को ।

श्री रामाबलार शास्त्री : जिन 1259 छोटे समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं उनमें से कितने समाचारपत्र और पीरियाडिकल्ज राजनीतिक दलों द्वारा संचालित हैं और उन दलों के नाम क्या हैं ?

श्री बर्मबीर सिंह : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है । इसके लिए नोटिस चाहिये ।

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI : In view of the fact that in the name of small newspapers a mushroom growth of yellow papers has cropped up in the recent years, may I know whether Government propose to take effective measures to maintain a high standard of journalism ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) :

I fully agree with the hon. Member that, in the name of helping the small and medium newspapers, we should not go all out to see that papers which are not genuine are helped. This is one thing which Government keeps in mind, and that is why, again and again, when the question of helping small and medium newspapers comes, we try to find out whether those papers which are to be helped are genuine or not. Certain criteria have been laid down because of that.

SHRI JAGANNATH RAO : May I know from the hon. Minister whether the large English newspaper which publish more than one edition a day get advertisements for each edition ? For instance, *Indian Express* publishes in six places, *Times of India* in three places and *Statesman* in three places.

Are advertisements given to each of the editions of these large newspapers ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Yes, Sir. Some of these newspapers which are coming out from different centres also get advertisements. but, we have tried to see that these papers which have got a chain of newspapers should not get so much of advertisements which are inconvenient to small and medium newspapers.

SHRI JAGANNATH RAO : What is the policy of the Government ?

श्री राम रतन शर्मा : क्या यह सच है कि जो समाचारपत्र सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करते हैं, उन्हें विज्ञापन नहीं दिये जाते ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह बिल्कुल सच नहीं है—समाचारपत्र सरकार की समालोचना करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर विज्ञापन देने की बात तय नहीं की जाती है ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : May I know the total value of advertisements given to newspapers, both large and small ? And since the hon. Minister has been pleased to say that the small newspapers get 60% of the total, I want to know whether it is in terms of value or in terms of number. Similarly, when it is said that 39.16% has been made available to the large newspapers, is it in terms of value or in numbers ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : It is in terms of value. That is, 60.84 percent were given to small and medium newspapers during the current year, i. e. upto the end of December and 39.16 percent were given to the big newspapers upto December 1971.

Setting up of Small Scale Industrial Units in West Beng 1 under 16-Point Programme

\*270. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the places where the small-scale industrial units planned to be set up in West